



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]
No. 412]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2003/वैशाख 17, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2003/VAISAKHA 17, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2003

का.आ. 502(अ).—अतः माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्किट बैंच, पोर्ट ब्लेयर ने रिट याचिका सं.2002 की 099, श्री पी. आर. सुबमणियम एवं अन्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य में 15 जनवरी 2003 को यह निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 150 के तहत एक अधिकरण गठित किया जाए तथा श्री पी. आर. सुबमणियम एवम 4 अन्य द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए विवाद को उस अधिकरण को सौंपा जाए।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत सरकार के राजपत्र -असाधारण में का. आ. 337(अ) दिनांक 28 मार्च 2003 के द्वारा एक अधिकरण का गठन किया गया था और श्री उमेश प्रसाद सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर 1963, सेवानिवृत्त), को उक्त अधिकरण में नियुक्त किया गया था। अब श्री उमेश प्रसाद सिंह ने अपरिहार्य व्यक्तिगत कारणों से अधिकरण के कार्य को निभाने में असमर्थता जतायी है।

अतः, इस मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत सरकार के राजपत्र -असाधारण में का. आ. 337(अ) दिनांक 28 मार्च 2003 को प्रकाशित हुई थी, का अतिक्रमण करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा एक अधिकरण का गठन करती है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में होगा और याचककर्ताओं द्वारा उठाये गये विवाद को सौंपती है और श्री बी. एन. मखीजा, योजना आयोग में पूर्व सलाहकार

(परिवहन) को उक्त अधिकरण में नियुक्त करती है, जो सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 माह के भीतर केन्द्र सरकार को अधिकरण का अधिनिर्णय प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिकरण को सौंपे गए विचारार्थ विषय और शर्तें अधोलिखित अनुसूची में दी गई हैं।

अनुसूची

(क) विचारार्थ विषय

आर. सुबमणियम एवं अन्य) द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2003 के पत्र में उठाए गए मुद्दों की जाँच करना तथा उपयुक्त सिफारिश करना।

(ख) शर्तें

- (i) अधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में होगा और इसे सचिवालय सहायता, शिपिंग मास्टर, मरकन्टाइल मैरीन डिपार्टमेंट, मुम्बई तथा नौवहन महानिदेशालय मुम्बई द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- (ii) अधिकरण द्वारा कार्यवाही करने पर तथा टी.ए. / डी. ए. के रूप में होने वाला व्यय तथा अन्य सम्बद्ध व्यय महानिदेशक नौवहन द्वारा यात्रा व्यय और कार्यालय व्यय शीर्ष से वहन किया जाएगा।
- (iii) अधिकरण, किसी व्यक्ति अथवा किसी श्रेणी के नाविक, अथवा नाविकों के किसी संघ, भारत में मामले से संबंधित व्यक्ति और पोत स्वामियों को, जहाँ मेंर्सस फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छटनी किये गये 5 नाविकी नियोजित थे, साक्ष्य देने और विचारार्थ विषय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से बुला सकता है। अधिकरण, यदि चाहें तो उन पदाधिकारियों को भी, नेशनल मैरीटाइम बोर्ड के समझौते तय कराने में शामिल होते हैं, स्पष्टीकरण, रिकार्ड्स की प्रस्तुति हेतु, अथवा किसी अन्य वांछित सूचना हेतु, अधिकरण की कार्यवाही के दौरान बुला सकता है।
- (iv) एक सदस्यीय अधिकरण के अध्यक्ष को प्रति बैठक अथवा प्रतिदिन 1500 रुपये दिये जाएंगे और वह नियमों के तहत देय टी.ए./डी.ए. के लिए भी प्रात्र होगी। (व्याख्या- एक बैठक - प्रत्येक बार एक बैठक पांच घंटे से कम नहीं होगी)
- (v) अधिकरण की कार्यावधि इसके गठन से तीन माह के लिए होगी।

अधिकरण के गठित होने के तीन माह के भीतर अधिकरण द्वारा सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।

[फा. सं. एस.आर.-11014/1/2003-एम.ए.]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2003

S.O. 502(E).— WHEREAS the Hon'ble High Court of Calcutta, Circuit Bench at Port Blair vide order dated 15.1.2003 in Writ Petition No. 099 of 2002 - Shri P.R. Subramaniam & others Versus Union of India & others has directed that a Tribunal may be constituted under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and refer the dispute raised by Shri P.R. Subramaniam and 4 others in this regard.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 One Person Tribunal was constituted and Shri Umesh Prasad Singh, IRS (Income-tax, 1963) (Retired) was appointed to the said Tribunal vide this Ministry's notification of even number published in the Gazette of India-Extraordinary under S.O. no. 337(E) dated 28th March, 2003. Now, Shri Umesh Prasad Singh has expressed his inability to discharge the duties of One Person Tribunal due to unavoidable personal reasons.

Now, therefore, in supersession of this Ministry's notification of even number published in the Gazette of India- Extraordinary under S.O. no. 337(E) dated 28th March, 2003 and in exercise of the powers conferred by section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal, with headquarters at Mumbai and refers the dispute raised by petitioner(s) and appoints Shri B.N. Makhija, former Advisor (Transport) in the Planning Commission to the said Tribunal who shall submit the award of the Tribunal to the central Government within 3 months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette. The Terms of Reference and the Terms & Conditions of said Tribunal are set out in the schedule given below.

SCHEDULE**(A) TERMS OF REFERENCE**

To examine the dispute raised in letter dated 3.2.2003 by Petitioner (Shri P.R.Subramaniam & others) in the above referred writ Petition seeking reinstatement and other relief for 5 seamen whose names appear in the annexure to that demand letter addressed to the Secretary, Ministry of Shipping, and to make appropriate recommendations.

(B) Terms and conditions

- (i) The Tribunal shall have its headquarters at Mumbai and secretarial assistance shall be provided by the Office of the Shipping Master /Mercantile Marine Department Mumbai and the Directorate General of Shipping, Mumbai.

- (ii) The expenditure incurred by the Tribunal in conducting the proceedings and TA/DA and Other allied expenses shall be met out of travel and office Expenses budget of DG(Shipping).
- (iii) The Tribunal may invite individuals or any class of seamen or any union of seamen, persons connected with the matter in India and owners of ships where petitioners, 5 seamen, retrenched by M/s. Fleet Management Private Ltd were employed, for giving evidence and for obtaining information relevant to the terms of reference. Tribunal may also invite the office bearers who are involved in concluding the NMB Agreements for any clarification and production of records, information as required, during the proceedings of the Tribunal.
- (iv) The chairperson of the One Person Tribunal Shall be paid Rs. 1500/- per sitting (or per day) and would also be entitled to TA/DA, as admissible under the rules. (Explanation: One sitting shall not be less than five hours on each occasion).
- (v) The term of the Tribunal shall be for 3 months from the date of its constitution.

The report will be submitted by the Tribunal to the Government within 3 months from the date of its constitution.

[F. No. SR-11014/1/2003-MA]

R. K. JAIN, Jt. Secy.